

श्री रामचंद्र जांगड़ा : मान्वयर, इसमें जो डेटाबेस है, वह 2011 की जनगणना का लिया गया है, जिसमें अभी तक टोटल जो सर्वेक्षण में आए हैं, वे लगभग 15 करोड़, 73 लाख आए हैं, जो कि हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से काफी कम है। मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहता हूं कि क्या इसके पुनः सर्वेक्षण की कोई योजना है, ताकि जो लाभ के पात्र हैं और जो वंचित हैं, उनको दोबारा लिया जा सके?

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise>]

***MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS**

MR. CHAIRMAN: The discussion on the Motion of Thanks on the President's Address initiated by Shrimati Geeta *alias* Chandraprabha ji concluded yesterday. Now the hon. Prime Minister will be responding to the debate.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने बीते दिनों कोरोना के इस कठिन काल खंड में भी देश में चहुँ दिशा में किस प्रकार से initiative लिए, देश के दलित, पीड़ित, गरीब, शोषित, महिला, युवा के जीवन के सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए, देश में जो कुछ भी गतिविधि हुई है, उसका एक संक्षिप्त खाका देश के सामने प्रस्तुत किया, और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है, संकल्प भी है और समर्पण भी है। अनेक माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। माननीय मल्लिकार्जुन खरगे जी ने कुछ देश के लिए, कुछ दल के लिए और कुछ खुद के लिए काफी बातें बताई थीं। आनन्द शर्मा जी ने भी, उन को ज़रा समय की तकलीफ रही, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की और उन्होंने यह कहा कि देश की उपलब्धियों को स्वीकारा जाए। प्रो. मनोज कुमार झा जी ने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण राजनीति से परे होना चाहिए, इसकी अच्छी सलाह भी दी। श्री प्रसन्न आचार्य जी ने "वीर बाल दिवस" और नेता जी से जुड़े कामों के संबंध में भी विस्तार से सराहना

* Further discussion continued on a Motion moved on 2nd February, 2022.

की। डा. फौजिया खान जी ने संविधान की प्रतिष्ठा को लेकर विस्तार से चर्चा की। हर सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी राजनैतिक सोच के आधार पर और राजनैतिक स्थिति के आधार पर अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का इसके लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल के आज़ादी के काल खंड में देश को दिशा देने के, देश को गति देने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं। और अब उन सबका लेखा-जोखा लेकर जो अच्छा है, उसे आगे बढ़ाना, जो कमियाँ हैं, उनको correct करना और जहाँ नये initiative लेने की आवश्यकता है, वे नये initiative लेना और देश जब आज़ादी के सौ साल मनाएगा, तब हमें देश को कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है और हम किन-किन योजनाओं के सहारे ले जा सकते हैं, इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम सभी राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अपने ध्यान को भी और देश के ध्यान को भी कि आने वाले पच्चीस सालों के लिए देश को कैसे आगे ले जाना है, इस पर केंद्रित करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे, उन संकल्पों में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, सबकी उन्नति होगी और उसके कारण, जो 75 साल की गति थी, उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं।

आदरणीय सभापति जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पिछले सौ साल में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है। महोदय, संकट की तीव्रता देखिए! माँ एक कमरे में बीमार है, लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए - पूरी मानव जाति के लिए यह कितना बड़ा संकट था! अभी भी यह संकट बहुरूपिया है, यह नये-नये रंग-रूप लेकर कभी न कभी, कुछ न कुछ आफतें लेकर आता है और पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति उससे जूझ रही है, हर कोई रास्ते खोज रहा है। दुनिया में जब कोरोना का प्रारंभ हुआ, तो चर्चा यही थी कि भारत का क्या होगा और भारत के कारण दुनिया की कितनी बरबादी होगी - इसी दिशा में चर्चा हो रही थी, लेकिन 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्तियों का सामर्थ्य और उन्होंने जीवन में जो भी उपलब्ध था, उसके बीच डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया, जिससे कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है। इसका गौरव किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, यह achievement देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता कि इसका यश लेने की कोशिश आप लोग भी करते, तो आपके खाते में कुछ जमा होता, लेकिन अब यह भी सिखाना पड़े! खैर, vaccination के समय में, अभी प्रश्न काल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात बताई है कि जिस प्रकार से भारत vaccine बनाने में, innovation में, research में और उसके implementation में सफल हुआ है, यह देखने योग्य है। आज भी दुनिया में vaccine के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन vaccine लेने से मेरा लाभ हो या न हो, लेकिन यदि मैं vaccine लगाऊंगा तो कम से कम मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा, इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को vaccine लेने के

लिए प्रेरित किया। यह भारत के मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है, जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता, तो लूं या न लूं का विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी dose लेनी है, तो मैं ले लूं और उसने dose ले ली। भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की यह भावना हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज शत-प्रतिशत डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी आदरणीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि उनके सामने हमारे frontline workers, हमारे healthcare workers, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है, उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी ही, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है।

आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के लिए इतने लंबे काल खंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। उनके घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, यह काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी कोरोना काल में, जबकि अनेक कठिनाइयाँ थीं, बंधन थे, इसके बावजूद प्रगति में रुकावटों के, बार-बार obstacles के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे। आज गरीब के घर का खर्चा भी लाखों में होता है, इसलिए जितने करोड़ों परिवारों को यह घर मिला है, हर गरीब परिवार आज लखपति कहा जा सकता है।

आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुँचाने का काम करके एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। इसी कोरोना काल में जब पहला lockdown आया, तब भी बहुत समझदारी के साथ, कड़ियों से चर्चा करने के बाद, थोड़े साहस की भी जरूरत थी कि गाँव में किसानों को lockdown से मुक्त रखा जाए, यह निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन हमने किया। उसका परिणाम यह आया कि हमारे किसानों ने कोरोना के इस काल खंड में भी bumper पैदावार की और M.S.P. में भी रिकॉर्ड खरीदी करके नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए गए। इसी कोरोना काल में infrastructure से जुड़े हुए कई projects पूरे किए गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे संकट के काल में infrastructure पर जो investment होता है, वह रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करता है। इसलिए हमने उस पर भी बल दिया, ताकि रोजगार भी मिलता रहे और हम सारे projects भी पूरे कर पाएँ। कठिनाइयाँ थीं, लेकिन हम उसको कर पाए।

इसी कोरोना काल में, चाहे जम्मू-कश्मीर हो, चाहे North-East हो, हर काल खंड में विस्तार से इनके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और हमने उसको चलाया है। इसी कोरोना काल खंड में हमारे देश के युवाओं ने खेल जगत के हर क्षेत्र में हिन्दुस्तान का तिरंगा, हमारा परचम लहराने का बहुत बड़ा काम किया और देश को गौरव दिलाया और हमारे युवाओं ने खेल जगत में जिस प्रकार

से प्रदर्शन किया है, कोरोना के इन सारे बँधनों के बीच उन्होंने अपनी तपस्या को कम नहीं होने दिया, अपनी साधना को कम नहीं होने दिया और देश का गौरव बढ़ाया है। आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में start-up भारत के युवाओं की एक पहचान बन गया है। आज, हमारे देश के युवा और start-up एक तरह से synonymous हो गए हैं, और start-up की दुनिया में हमारे युवा हिन्दुस्तान को top three में जगह दिलवा पाए हैं।

आदरणीय सभापति जी, इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G-20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे सामाजिक जीवन के अनेकानेक विषयों में काम करने की बात हो या दुनिया के 150 देशों तक दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक leadership role लिया है। आज भारत की इस leadership की चर्चा पूरी दुनिया में है, उसे स्वीकृति मिली है।

आदरणीय सभापति जी, जब संकट का काल होता है, तो चुनौतियां अपार होती हैं। विश्व की हर शक्ति अपने ही बचाव में लगी होती है, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है। ऐसे कालखंड के उन संकटों से बाहर निकालने के लिए, आज मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता के कुछ शब्द याद आ रहे हैं, जो हम सबके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। माननीय अटल जी ने लिखा था :

*"व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा,
किंतु चीर कर तम की छाती,
चमका हिन्दुस्तान हमारा।
शत-शत आघातों को सह कर,
जीवित हिन्दुस्तान हमारा।
जग के मस्तक पर रोली सा,
शोभित हिन्दुस्तान हमारा।"*

अटल जी के ये शब्द आज के इस कालखंड में भारत की सामर्थ्य का परिचय कराते हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में सभी क्षेत्रों में रुकावटों के बीच भी आगे बढ़ने के भरपूर प्रयास किए गए। लेकिन इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे, जिन पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि वह व्यापक जनहित में आवश्यक था, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक था। कोरोना काल में जिन विशेष क्षेत्रों पर फोकस किया गया, उनमें से दो की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। एक एमएसएमई सेक्टर है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक क्षेत्र है, जिसमें हमने लोगों को शिक्षित किया। इसी प्रकार से खेती-बाड़ी का क्षेत्र है। उसमें भी कोई रुकावट न आए, इसको भी सुनिश्चित किया गया। उसी की वजह से, जैसा मैंने वर्णन किया, बम्पर क्रॉप हुई और सरकार ने रिकॉर्ड खरीद भी की। महामारी के बावजूद गेहूं और धान की खरीद के नये रिकॉर्ड बने, किसानों को ज्यादा एमएसपी मिला, वह भी 'Direct Benefit Transfer Scheme' के तहत मिला और पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में

जमा हुआ। मैंने पंजाब के लोगों के कई वीडियो देखे, चूंकि पंजाब में पहली बार 'Direct Benefit Transfer Scheme' के माध्यम से पैसा गया। उन्होंने कहा, मेरे खेत का साइज तो उतना ही है, हमारी मेहनत भी उतनी ही है, लेकिन खाते में एक-साथ इतना रुपया आता है, यह जिन्दगी में पहली बार देखा है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*

श्री नरेन्द्र मोदी : इससे संकट के समय में किसानों के पास कैश की सुविधा रही। ऐसे कदमों से ही इतने बड़े सेक्टर को shocks और disruptions से हम बचा पाए। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, यह उन सेक्टर्स में था, जिनको आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सबसे अधिक लाभ मिला। अलग-अलग मंत्रालयों ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की, उससे मेन्युफैक्चरिंग को बल मिला, भारत अब लीडिंग मोबाइल मेन्युफैक्चर बन गया है और एक्सपोर्ट में भी उसका योगदान बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी के क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम उत्साहजनक परिणाम दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर मेन्युफैक्चरिंग, और वह भी ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होती है, तो स्वाभाविक है कि दुनिया के देशों से ऑर्डर्स भी मिलते हैं, ज्यादा अवसर भी मिलते हैं। सच तो यह है कि इंजीनियरिंग गुड्स, जो बड़ी मात्रा में एमएसएमईज बनाती हैं, इस समय एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा बढ़ा बना है, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, यह भारत के लोगों के कौशल और भारत के एमएसएमईज की ताकत को प्रदर्शित करता है।

हमारी डिफेंस मेन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखें। हम यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। एमओयूज जो हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं, एमएसएमई क्षेत्र के लोग डिफेंस के सेक्टर में आ रहे हैं, यह अपने आपमें उत्साहवर्धक है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है और देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे एमएसएमई क्षेत्र के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं और आगे आ रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, एमएसएमई के कुछ GeM के माध्यम से सरकार में जो सामान की खरीददारी होती है, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया है और उस प्लेटफॉर्म के कारण आज बहुत सुविधा मिली है। उसी प्रकार से हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है और वह निर्णय यह है कि सरकार में 200 करोड़ रुपये तक के जो टेंडर होंगे, वे टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे, उसमें हिन्दुस्तान के लोगों को ही अवसर दिया जाएगा, जिसके कारण हमारे एमएसएमई सेक्टर को और उसके द्वारा हमारे रोजगार को बल मिलेगा।

आदरणीय सभापति जी, इस सदन में आदरणीय सदस्यों ने रोजगार के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिये हैं। कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, यह जानने के

लिए EPFO payroll सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग एक करोड़ बीस लाख नये लोग EPFO के payroll पर जुड़े और यह न भूलें कि ये सारी formal jobs हैं, मैं informal की बात नहीं कर रहा हूं और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार job market में उनकी entry हुई है।

आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में Covid restrictions खुलने के बाद हायरिंग दोगुना बढ़ गई है। NASSCOM की रिपोर्ट में भी इसी trend की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद direct-indirect जॉब्स, यह NASSCOM का कहना है कि 27 लाख जॉब्स IT sector में आई और यह सिर्फ स्किल की दृष्टि से नहीं, बल्कि उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है। Manufacturing बढ़ने की वजह से भारत के Global exports में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा-सीधा होता है। आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2021 में, यानी सिर्फ 1 साल में भारत में जितने unicorns बने हैं, वह पहले के वर्षों में बने कुल unicorns से भी ज्यादा हैं और ये सब यदि रोजगार की गिनती में नहीं आते हैं, तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की ही चर्चा मानी जाती है।

आदरणीय सभापति जी, कई माननीय सदस्यों ने महंगाई की चर्चा की है। 100 साल में आई कोरोना की इस भयंकर वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अगर महंगाई की बात करें, तो अमेरिका 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का दौर झेल रहा है, ब्रिटेन 30 साल में आज सबसे अधिक महंगाई की मार से परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां Euro currency है, वहां महंगाई की दर historically highest है, उच्चतम है। ऐसे माहौल में भी, महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है और ईमानदारी से कोशिश की है। वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक यह दर 4 से 5 प्रतिशत के आस-पास थी। इसकी तुलना ज़रा यूपीए के दौर से करें, तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है! यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। हम आज एकमात्र बड़ी economy हैं, जो high growth और medium inflation का अनुभव कर रहे हैं, बाकी यदि दुनिया की economy को देखें, तो वहां की अर्थव्यवस्था में या तो ग्रोथ स्लो हुई है या फिर महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है।

आदरणीय सभापति जी, इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीर पेश की और पेश करने में आनंद आ रहा था, ऐसा भी लग रहा था। मैं जब इस प्रकार की निराशाएं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जय-पराजय होती रहती है, उससे छाई हुई व्यक्तिगत जीवन की निराशा को कम से कम देश पर नहीं थोपना चाहिए। मैं नहीं जानता, हमारे यहां गुजरात में एक बात है - शरद राव जी जानते होंगे, वहां महाराष्ट्र में भी होगी - कहते हैं कि जब हरियाली होती है, खेत हरे-भरे होते हैं, उस वक्त किसी ने वह हरियाली देखी हो

और उसी समय by accident अगर उसकी आंखें चली जाएं, तो जीवन भर उसे वह हरा वाला जो आखिरी चित्र है, वह दिखाई देता है।

12.00 Noon

वैसा 2013 तक जिस दुर्दशा में समय गुजारा और 2014 में अचानक देश की जनता ने जो रोशनी की, अगर उसमें किसी की आंखें चली गई हैं, तो उनको पुराने दिन ही दिखते हैं।
...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, 'महाजनो येन गतः स पन्थाः', अर्थात् महाजन लोग, बड़े लोग जिस पथ पर जाते हैं, वही मार्ग अनुकरणीय होता है। मैं इस सदन में एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ कोई भी हो, वह किसी भी दिशा में बैठा हो, उधर हो, यहाँ हो या कहीं हो, लेकिन वह जनप्रतिनिधि है, वह अपने आप में, छोटा हो, बड़ा हो, क्षेत्र का लीडर होता है, वह क्षेत्र का नेतृत्व करता है। जो भी उसका कमांड एरिया होगा, वहाँ के लोग उसको देखते हैं, उसकी बातों को फॉलो करते हैं। अब ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि हम सत्ता में हैं, तो लीडर हैं और वहाँ बैठ गए, तो अरे, क्या हो गया - ऐसा नहीं होता है। आप कहीं पर भी हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप सच्चे अर्थ में लीडर हैं। अगर लीडर इस प्रकार से सोचेगा, ऐसी निराशा से भरा हुआ लीडर होगा, तो क्या होगा? क्या यहाँ बैठें, तभी देश की चिंता करनी है और अगर वहाँ बैठें, तो देश और अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता नहीं करनी है - क्या ऐसा होता है? अगर आप किसी से नहीं सीखते हैं, तो आप शरद राव जी से सीखिए। मैंने देखा है कि शरद राव जी इस उम्र में भी, अनेक बीमारियों के बीच भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप निराश होते हैं, भले ही आपका क्षेत्र अब कम हो गया होगा, लेकिन जो भी होगा...(व्यवधान)...

श्री सभापति : इस तरह से बैठ कर running commentary करना उचित नहीं है, यह पद्धति नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोदी : यह हम सबका दायित्व है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : सुनिए, जब आपको मौका मिला, तब आपने बोला।...(व्यवधान)...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : *

श्री सभापति : खरगे जी, आपको बुलाया नहीं गया है। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।...(व्यवधान).... यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

* Not recorded.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : *

श्री नरेन्द्र मोदी : खरगे जी, आप भी अधीर रंजन जी जैसी गलती करते हैं। आप थोड़ा पीछे देखिए, जयराम जी ने पीछे जाकर इस काम के लिए दो-तीन लोगों को तैयार किया हुआ है। आप प्रतिष्ठा से रहिए, पीछे रखी है व्यवस्था, जयराम जी बाहर जाकर सूचना लेकर आए हैं, वे समझा रहे थे। अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। आप सम्माननीय नेता हैं।...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश की सामर्थ्य को कम नहीं आँकना चाहिए। हमें देश की सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरवगान करना चाहिए, यह देश के लिए बहुत आवश्यक होता है।

आदरणीय सभापति जी, सदन में हमारे एक साथी ने कहा, 'Vaccination is not a big deal'. मैं यह देख कर हैरान हूँ कि कुछ लोगों को भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि उपलब्धि नहीं लग रही है। एक साथी ने यह भी कहा कि टीकाकरण पर व्यर्थ खर्च हो रहा है। यह देश सुनेगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेगा!

आदरणीय सभापति जी, जब से कोरोना मानव जाति पर संकट पैदा कर रहा है, सरकार ने देश और दुनिया में उपलब्ध हर संसाधन जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की है। हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए हमारी जितनी भी सामर्थ्य थी, समझ थी, शक्ति थी, हमने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। जब तक महामारी रहेगी, तब तक सरकार को गरीब से गरीब परिवार का जीवन बचाने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा, सरकार उसे खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ दलों के बड़े नेताओं ने बीते दो सालों में जो अपरिपक्वता दिखाई है, उससे देश को भी बहुत निराशा हुई है। हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ में खेल खेले गए हैं। भारतीय वैक्सीन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। थोड़ा सोचिए - जो आपने पहले कहा था और आज जो हो रहा है, दोनों को साथ मिलाकर देखिए। हो सकता है कि सुधार की संभावना हो, तो कुछ काम आ जाएगा। आदरणीय सभापति जी, इस देश की जनता जागरूक है और मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूँ कि जब उनके हर छोटे-मोटे नेताओं ने ऐसी गलती की, तब भी उन्होंने इस संकट के समय ऐसी बातों को कान पर नहीं दिया और वैक्सीन के लिए कतार में खड़े रहकर वैक्सीन ली। अगर यह न हुआ होता, तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता, लेकिन अच्छा हुआ, देश की जनता कुछ नेताओं से भी आगे निकल गई। यह देश के लिए अच्छा है।

आदरणीय सभापति जी, एक प्रकार से इस पूरे कोरोना काल को मैं federal structure का उत्तम उदाहरण कह सकता हूँ। 23 बार - शायद किसी एक प्रधान मंत्री को एक कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों की इतनी मीटिंग्स करने का अवसर नहीं आया होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ 23 मीटिंग्स

की गई और विस्तार से चर्चाएं की गई। मुख्यमंत्रियों के सुझाव और भारत सरकार के पास जो जानकारी थी, उन पर मिलजुल करके काम किया गया। चूँकि सदन में राज्यों से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता बैठे हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इस कालखंड में 23 मीटिंग्स करना, विस्तार से चर्चा करके रणनीति बनाना, सबको on board लेकर चलना और चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय स्वराज संस्था की इकाइयाँ हों, सबने मिलकर प्रयास किया है। हम किसी के योगदान को कम नहीं आँकते हैं। हम तो इसे देश की ताकत मानते हैं, लेकिन आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जब कोरोना की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, सरकार की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन देना था, तब एक तरफ से कोशिश की गई कि कुछ दल न जाएं। उन्हें समझाने की कोशिश हुई और खुद भी नहीं आए, ऑल पार्टी मीटिंग का बहिष्कार किया। मैं शरद राव जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। शरद राव जी ने कहा, 'देखिए, यह कोई यूपीए का निर्णय नहीं है। मैं जिस-जिस से कह सकता हूँ, मैं कहूँगा' और शरद राव जी आए। टीएमसी सहित सभी दल के लोग आए और उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए। यह संकट देश पर था, मानव जाति पर था। आपने उसका भी बहिष्कार किया। यह पता नहीं कि आपको ऐसी एडवाइस कौन देता है, आप कहाँ से सलाह लेकर आते हैं! ऐसा करके आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। देश रुका नहीं, देश चल पड़ा, आप अटक गए और हरेक को आश्चर्य हुआ। आप दूसरे दिन के अखबार देख लीजिए, आपकी क्या आलोचना हुई है कि ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा काम, लेकिन...

आदरणीय सभापति जी, हमने holistic healthcare पर फोकस किया। आधुनिक चिकित्सा परम्परा, भारतीय चिकित्सा पद्धति, दोनों को साथ लिया। आयुष मंत्रालय ने भी इस समय बहुत काम किया। सदन में कभी-कभी ऐसे मंत्रालयों की चर्चा भी नहीं होती है, लेकिन यह देखना होगा कि आज विश्व में -- हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग बताएँगे -- हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, इस कोरोना ने दुनिया के लोगों को भारत की उपचार पद्धति की ओर आकर्षित किया है, यह उसका परिणाम है। आज कोरोना कालखंड में भारत ने अपने फार्मा उद्योग को भी सशक्त किया है। पिछले सात साल में हमारा जो आयुष का उत्पादन है, उसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है और वह नये-नये डेस्टिनेशंस पर पहुँच रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसने विश्व में अपनी एक पहचान बनानी शुरू की है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, जहाँ-जहाँ हमारा परिचय हो, इस बात पर बल दें, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र दबा हुआ है। अगर हम इस पर थोड़ा बल देंगे, तो यह ऐसा समय है, जब उसकी स्वीकृति बन जाएगी और इससे यह होगा कि भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की परम्परा है, ताकत है, वह दुनिया में पहुँचेगी और काम होगा।

आदरणीय सभापति जी, 'आयुष्मान भारत' के तहत 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आज कार्यरत हैं और हर प्रकार की आधुनिक से आधुनिक सेवाएँ देने के लिए उनको सजाया जा रहा है। ये सेंटर्स गाँव और घर के पास ही फ्री टैस्ट समेत बेहतर प्राइमरी हेल्थकेयर सुविधा दे रहे

हैं। ये सेंटर्स कैंसर, डायबटीज और दूसरी गंभीर बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने में मदद कर रहे हैं। अभी 80,000 सेंटर्स बने हैं और इनको हम और बढ़ाने की दिशा में तेज गति से काम कर रहे हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण बीमारियों में भी, गंभीर बीमारियों में भी उनको स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना है।

आदरणीय सभापति जी, वैसे पुरानी परम्परा यह थी कि बजट के पहले कुछ टैक्स लगा दो, ताकि उस पर चर्चा न हो, वह बजट में न दिखे और उस दिन शेयर मार्किट गिर न जाए। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उल्टा किया। हमने बजट के पहले 64,000 करोड़ रुपये 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए राज्यों के अंदर बाँटे। अगर हम यह चीज़ बजट में रखते, तो बजट और ज्यादा शानदार दिखता। यह शानदार तो है ही, यह और शानदार दिखता, लेकिन उस मोह में रहने के बजाय कोरोना के समय इसकी तत्काल व्यवस्था करने के लिए हमने इसको पहले किया और 64,000 करोड़ रुपये इस काम के लिए दिए।

आदरणीय सभापति जी, इस बार खरगे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे। वे मुझे तो यह कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूँ, इधर-उधर न बोलूँ, लेकिन वे क्या बोले हैं, उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, यह सदन में ऐसे ही हँसी-मज़ाक में कही गई बात नहीं थी। यह उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है और वह यह है कि कुछ लोग यही मानते हैं कि हिन्दुस्तान 1947 में पैदा हुआ और उसी के कारण यह समस्या होती है। ...**(व्यवधान)**... इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिनको 50 साल काम करने का मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियाँ पैदा हुई हैं। यह डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है ...**(व्यवधान)**... और आपको, 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरवगान नहीं करना चाहिए।...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, ये वर्ष 1947 में पैदा हुए हैं, जो ऐसी सोच वाले लोग हैं, उन्हें दुनिया के सामने यह बात गाजे-बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, लेकिन वे कहने से कतरा गए हैं। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत - Mother India, Mother of Democracy है। डेमोक्रेसी और डिबेट भारत में सदियों से चल रही है और कांग्रेस की कठिनाई यह है कि dynasty के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है और पार्टी में, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वे इस बात को समझें कि भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, यह मानना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... और पार्टी में कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है, तो सबसे पहली casualty talent की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाए।

आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती, तो क्या होता। India is Indira, Indira is India, यह इसी सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी जी की इच्छा थी - क्योंकि महात्मा गांधी जी को मालूम था कि इनके रहने से क्या-क्या होने वाला है इसलिए उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो - यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगर महात्मा गांधी जी की इच्छा के अनुसार हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती, तो क्या होता - लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, भारत विदेशी चश्मे के बजाय, स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती, तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती, तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती, तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती, तो सिखों का नरसंहार न होता, सालों साल पंजाब आतंक की आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती, तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती, तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। ...**(व्यवधान)**... आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : मोदी साहब, आप इस तरह से भाषण करेंगे ...**(व्यवधान)**... यहां सदन में ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : खरगे जी, आपने भी एक घंटे तक बोला है। ...**(Interruptions)**.. Khargeji, you are the Leader of the Opposition. ...**(Interruptions)**.. Please understand. You also spoke for one hour and six minutes. यह पद्धति नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेन्द्र मोदी : इसलिए आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही तो देश का विकास नहीं होने दिया।...**(व्यवधान)**... अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, ...**(व्यवधान)**...नेशन पर आपत्ति है, यदि नेशन की कल्पना गैर-संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**... अपने पूर्वजों की गलती को जरा सुधार दीजिए। ...**(व्यवधान)**...आदरणीय सभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। Nothing will go on record without my permission. ...**(Interruptions)**..

श्री नरेन्द्र मोदी : आदरणीय सभापति जी, यहां पर फेडरेलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टी.एम.सी. और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां बड़ी-बड़ी बातें कीं। **...(व्यवधान)...** जरूरी भी हैं, क्योंकि यह राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का सदन है, लेकिन सभी साथियों को, आदरणीय सभापति जी, **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record without my permission. **...(Interruptions)...** Without my permission nothing will go on record. **...(Interruptions)...** No comments will go on record. **...(Interruptions)...** प्लीज़ बैठ जाइये। Nothing will go on record, except what is permitted by the Chair. **...(Interruptions)...** Whatever is permitted by the Chair will go on record. **...(Interruptions)...** No comment, no noise, no demonstration will go on record. **...(Interruptions)...** बैठ जाइये। Please, the Prime Minister is intervening. I have permitted it. **...(Interruptions)...** It will only go on record. रामदास जी, आप चिन्ता मत करिये। जिसे जाना है, वह जायेगा, आप क्यों चिन्ता करते हैं? प्रधान मंत्री जी, आप देखिए, **...(व्यवधान)...**

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसके विरोध में हम लोग सदन से वॉक- आउट करते हैं। **...(व्यवधान)...**

(इस समय, कुछ माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये)

MR. CHAIRMAN: **...(Interruptions)...** That is your comment. **...(Interruptions)...** Let the people decide. **...(Interruptions)...** When we speak, we don't bother about all this. **...(Interruptions)...** प्रधान मंत्री जी।

श्री नरेन्द्र मोदी : धन्यवाद। आदरणीय सभापति जी, लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रही है। आदरणीय सभापति जी, फेडरेलिज्म को लेकर कांग्रेस, टी.एम.सी. और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां कई विचारों को प्रस्तुत किया है। यह बहुत स्वाभाविक है और इस सदन में इसकी चर्चा होना और भी स्वाभाविक है, क्योंकि यहां राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन इस सदन में हमें मिलता रहता है। लेकिन जब ये बात करते हैं, तब मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि फेडरेलिज्म के सम्बन्ध में हमारे जो कुछ भी विचार हैं, उस संबंध में कभी बाबा साहेब अम्बेडकर को जरूर पढ़ें, बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों का स्मरण करें। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में जो कहा था, उसी को मैं क्वोट कर रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, 'यह फेडरेशन एक यूनियन है, क्योंकि यह अटूट है। प्रशासनिक सुविधा हेतु देश और लोगों को प्रशासन के लिए

विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है।' उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं और नेशन की कल्पना को स्पष्ट किया है। यह बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा है। मैं समझता हूं कि Federalism को समझने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के इतने गहन विचारों से अधिक किसी भी बात के लिए मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेषता यह है कि हमारे देश में क्या हुआ है? Federalism के बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं। क्या हम वे दिन भूल गए हैं, जब एयरपोर्ट पर जरा-सी बातों के लिए मुख्यमंत्रियों को हटा दिया जाता था! आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री Shri T. ANJIAH के साथ क्या हुआ था, इस सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधान मंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया, तो उनको बरखास्त कर दिया गया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। इसी प्रकार कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था और वह भी तब, जब वे बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है। हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट और regional aspirations, उस के बीच में कोई conflict नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि regional aspirations को उतनी ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए। भारत की प्रगति तब होगी, जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए regional aspirations को एड्रेस करे, यह दायित्व बनता है।

जब हम इस बात को कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, तो इसकी यह भी शर्त है कि जब राज्य प्रगति करते हैं, तब देश की तरक्की होती है। राज्य प्रगति न करें और देश की तरक्की के लिए हम सोचें, तो यह नहीं हो सकता है। इसलिए पहली शर्त यह है कि राज्य प्रगति करें, तब देश की तरक्की होती है। जब देश की तरक्की होती है, देश समृद्ध होता है, देश के अंदर समृद्धि आती है, तो वह समृद्धि राज्यों में percolate होती है, और इसके कारण देश समृद्ध बनता है। इस सोच के साथ हम चलते हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं गुजरात में था, तब दिल्ली सरकार के द्वारा मुझ पर क्या-क्या जुल्म हुए हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, गुजरात के साथ क्या-क्या नहीं हुआ है! लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं मुख्य मंत्री के नाते हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, कि देश के विकास के लिए गुजरात का विकास है। दिल्ली में किसकी सरकार है, हम यह सोचकर नहीं चलते थे। देश के विकास के लिए, गुजरात का विकास, और यही Federalism में हम सबका यही दायित्व बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करें, ताकि दोनों मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। यही तरीका सही तरीका है और उसी रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है।

और यह बहुत दुखद बात है कि जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला, और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे-कैसे दमन किए थे। यहां सब भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कैसे-कैसे दमन किए थे! करीब-करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई राज्य सरकारों को

उखाड़ कर फेंक दिया गया था। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान नहीं किया। वह कौन प्रधान मंत्री है, जिसने अपने कालखंड में राज्य की पचास सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया था! आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों का जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है और उसी की सज़ा आज उनको भुगतनी पड़ रही है, देश उनको स्वीकार नहीं कर रहा। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जो high command हैं, कामों को लेकर उनकी नीति तीन प्रकार से चलती है - एक, पहले discredit करो, फिर destabilise करो और फिर dismiss करो। इसी तरीके से अविश्वास पैदा करो, अस्थिर करो और फिर बरखास्त करो, इन्हीं बातों को लेकर ये चले हैं।

आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी देवी लाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, पंजाब में सरदार बादल जी की सरकार को किसने बरखास्त किया था, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने dirty tricks का उपयोग किया था, कर्णाटक में रामकृष्ण हेगड़े और एस. आर. बोम्मई की सरकार को किसने गिराया था, पचास के दशक में केरल की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था, उस कालखंड में पचास साल पहले, तमिलनाडु में emergency के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था, 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने dismiss किया था, आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी और वह भी तब, जब वे बीमार थे! वह कौन सा दल है, जिसने मुलायम सिंह यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था, क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे! कांग्रेस ने अपने नेताओं तक को नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश ने कांग्रेस की सरकार में अहम भूमिका निभाई। उसने क्या किया - जिस आंध्र प्रदेश ने यहां सत्ता में उनको बैठने के लिए मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची का स्प्रे किया गया, कोई discussion नहीं हुआ। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? अटल जी की सरकार ने भी तीन राज्य बनाए थे। राज्य बनाने का हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने तीन राज्य बनाए थे - छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, सारा निर्णय शांति से हुआ और सबने मिल-बैठकर कर निर्णय किया। आंध्र और तेलंगाना का भी यह हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं हैं, यह साथ मिलकर किया जा सकता था, लेकिन आपके अहंकार और सत्ता के नशे ने देश के साथ कटुता पैदा की और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच वे कटुता के बीज तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है और हमें समझा रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, हम cooperative federalism के साथ-साथ एक नए बदलाव की ओर चले हैं और हमने cooperative competitive federalism की बात कही है। हमारे राज्यों के बीच में विकास के लिए स्पर्धा हो, तंदुरुस्त स्पर्धा हो और हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। किसी भी राज्य

में कोई भी दल राज क्यों न करता हो, उसको प्रोत्साहन देना हमारा काम है और हम दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूँ। GST Council की रचना अपने आप में भारत के सशक्त federalism के लिए एक उत्तम structure का नमूना है। Revenue के अहम निर्णय GST Council में होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री सभी equal table पर बैठकर निर्णय करते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, सब साथ मिलकर यह कार्य करते हैं। देश को गर्व होना चाहिए, इस सदन को ज्यादा गर्व होना चाहिए कि GST के सैकड़ों निर्णय हुए हैं, सब के सब सर्वानुमति से हुए हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री ने मिलकर किए हैं। Federalism का इससे बड़ा उत्तम स्वरूप क्या हो सकता है? कौन इसका गौरव नहीं करेगा? लेकिन हम इसका भी गौरव नहीं करते हैं!

आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण federalism का देना चाहता हूँ। हमने देखा कि जैसे सामाजिक न्याय देश में बहुत अनिवार्य होता है, वरना देश आगे नहीं बढ़ता है, वैसे ही क्षेत्रीय न्याय भी उतना ही जरूरी होता है। अगर कोई क्षेत्र विकास में पीछे रह जाएगा, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है और इसीलिए हमने Aspirational Districts की एक योजना बनाई। हमने देश में 100 से अधिक Aspirational Districts चुने, वे अलग-अलग पैरामीटर्स के आधार पर चुने गए, राज्यों के साथ मशविरा करके चुने गए। जो 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वे राज्य के जो एवरेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके बराबर तो कम से कम आ जाएं, ताकि बोझ कम हो जाए, इसलिए इस काम को हमने किया। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहूंगा, बड़े गौरव के साथ कहूंगा कि इस योजना का विचार भले ही भारत सरकार को आया हो, लेकिन एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने इसको own किया, 100 से अधिक जिलों की स्थिति बदलने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जिला इकाई आज मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें सभी दलों की सरकार वाले राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल भारतीय जनता पार्टी की राज वाली सरकारें हैं। सबने मिलकर इतने उत्तम परिणाम दिए हैं कि बहुत कम समय में Aspirational Districts कई पैरामीटर में अपने राज्य की एवरेज से भी कुछ आगे निकल गए हैं। मैं समझता हूँ कि यह उत्तम से उत्तम काम है और मैं बताऊँ कि कुछ आकांक्षी जिले Aspirational Districts हैं, उनमें पहले की तुलना में चार गुना ज्यादा जन-धन अकाउंट्स खोलने का काम किया है। हर परिवार में शौचालय मिले, बिजली मिले, इसके लिए भी उत्तम काम इन Aspirational Districts में सभी राज्यों ने मिलकर किया है। मैं समझता हूँ कि यही फेडरल स्ट्रक्चर का उत्तम उदाहरण है - देश की प्रगति के लिए फेडरल स्ट्रक्चर की ताकत का उपयोग होना - यह उसका उदाहरण है।

आदरणीय सभापति जी, मैं आज बताना चाहता हूँ कि कैसे राज्यों की आर्थिक मदद होती है, नीतियों में बदलाव लाने से कैसे राज्यों में परिवर्तन आता है, उसका भी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। वह भी एक समय था जब हमारे प्राकृतिक संसाधन सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरियां भरने के लिए काम आते थे। यह दुर्दशा हमने देखी है, उसकी चर्चाएं बहुत चली हैं। अब यह सम्पदा राष्ट्र का खजाना भर

रही है। हमने कोयला और माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं। हमने पारदर्शी प्रक्रिया के साथ खनिज संसाधनों का ऑक्शन किया। हमने रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को जारी रखा, जैसे वैध लाइसेंस की बिना जांच के ट्रांसफर, 50 प्रतिशत प्रोड्यूसर्स की ओपन मार्केट में बिक्री, अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन पर 50 प्रतिशत रिबेट। बीते एक साल में माइनिंग रेवेन्यू लगभग 14,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। ऑक्शन से जितना भी रेवेन्यू आया, वह राज्य सरकारों को मिला है - यह निर्णय किया गया है और यह सबसे बड़ी बात है। ये सुधार जो लागू किए गए हैं, इनसे राज्यों का भला हुआ है और राज्य का भला होने में देश का भला होता ही है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और ओडिशा इन रिफॉर्म्स को लागू करने में अग्रिम राज्य रहा है। मैं ओडिशा के मुख्य मंत्री जी को अभिनंदन देता हूं कि उनकी सरकार ने सारे रिफॉर्म्स में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है।

आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह भी चर्चा हुई कि हम इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार बोला जाता है, बाहर भी बोला जाता है और कुछ लोग लिखते भी हैं। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सलस के चंगुल में फंस गई है। उनके पूरे सोचने के तरीकों पर अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया और इसलिए उनकी सारी सोच, गतिविधि destructive बन गई है, यह देश के लिए चिंता का विषय है और इसके बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अर्बन नक्सल ने बहुत चालाकीपूर्वक कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठाकर उसके मन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उसके विचार-प्रवाह पर कब्जा कर लिया है। और उसी के कारण वे बोल रहे हैं कि इतिहास बदल रहा है।

आदरणीय सभापति जी, हम सिर्फ कुछ लोगों की याददाश्त को ठीक करना चाहते हैं और उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। हम कोई इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास कुछ ही सालों से शुरू होता है, हम उसको जरा पहले ले जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको 50 साल के इतिहास में ही मजा आता है, तो हम उसको सौ साल तक ले जा रहे हैं। किसी को 100 साल तक मजा आता है, तो हम 200 साल के इतिहास में ले जा रहे हैं, किसी को 200 में मजा आता है तो हम 300 तक ले जाते हैं और जब 300-350 तक ले जाएंगे, तो छत्रपति शिवाजी का नाम आएगा ही आएगा। हम तो उनकी मेमोरी को सतेज कर रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, तो इसका क्या करें? इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसके बड़े पहलू हैं, बड़े उतार-चढ़ाव हैं और हम इतिहास के एक दीर्घकालीन काल खंड को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौरवपूर्ण इतिहास को भुला देना इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, यह हम अपना दायित्व समझते हैं। और इसी इतिहास से सबक लेते हुए हमारा प्रयास आने वाले पच्चीस सालों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विश्वास पैदा कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह अमृत काल खंड अब इसी से आगे बढ़ने वाला है। इस अमृत काल खंड में हमारी बेटियों, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे गाँव, हमारे दलित, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े और समाज के

हर तबके का योगदान हो, उनकी भागीदारी हो, हम उसको लेकर आगे बढ़ें। कभी-कभी जब हम 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम की ओर देखेंगे, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम में जो योगदान दिया गया है, वह कभी हमें पढ़ने को नहीं मिला है। इतने महान स्वर्णिम पृष्ठों को हम कैसे भूल सकते हैं? हम इन चीजों को याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि देश आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, देश आगे बढ़े।

आदरणीय सभापति जी, महिलाओं का सशक्तिकरण भी हमारे लिए एक प्राथमिकता है। भारत जैसे देश में, हमारी विकास यात्रा में जो सबके प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं और बहनें हैं, देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या है। और इसलिए भारत के समाज की विशेषता है कि वह अपनी परंपराओं में सुधार करता है, बदलाव भी करता है, यह एक जीवंत समाज है। हर युग में ऐसे महापुरुष निकलते हैं, जो हमारी बुराइयों से समाज को मुक्त करने के लिए प्रयास करते हैं। और हम जानते हैं कि महिलाओं के संबंध में भी भारत में केवल आज ही चिंतन नहीं होना है, बल्कि पहले से हमारे यहाँ पर चिंतन हो रहा है, उनके सशक्तिकरण को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर हमने maternity leave बढ़ाई है, तो यह एक प्रकार से हमारा महिलाओं के सशक्तिकरण और परिवार के सशक्तिकरण का प्रयास है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना का परिणाम है कि जेंडर रेश्यो में हमारे यहां जो असंतुलन था, उसमें काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें आज हमारे यहाँ कुछ स्थानों पर तो पुरुषों से अधिक माताओं, बहनों की संख्या बढ़ रही है। यह बड़े आनंद का विषय है, गौरव का विषय है। जो बुरे दिन हमने देखे थे, हम उसमें से बाहर आए हैं और इसलिए हमें प्रयास भी करना चाहिए।

आज एनसीसी में हमारी बेटियाँ हैं, सेना में हमारी बेटियाँ हैं, वायु सेना में हमारी बेटियाँ हैं, नौ सेना में हमारी बेटियाँ हैं। तीन तलाक की कुप्रथा को हमने खत्म किया है। मैं जहाँ जाता हूँ, वहाँ मुझे उन माताओं, बहनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जब तीन तलाक की प्रथा खत्म होती है, तब सिर्फ बेटियों को न्याय मिलता है - ऐसा नहीं है, बल्कि उस पिता को भी न्याय मिलता है, उस भाई को भी न्याय मिलता है, जिसकी बेटी तीन तलाक के कारण घर लौटकर आती है, जिसकी बहन तीन तलाक के कारण घर लौटकर आती है, इसलिए यह पूरे समाज के कल्याण के लिए है। यह सिर्फ महिलाओं के लिए है और पुरुषों के खिलाफ है - ऐसा नहीं है। यह मुसलमान पुरुष के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि वह भी किसी बेटी का बाप है, वह भी किसी की बेटी का भाई है, और इसलिए यह उसका भी भला करता है, उसको भी सुरक्षा देता है। कुछ कारणों से लोग बोल पाएं या न बोल पाएं, लेकिन इस बात को सभी लोग गौरव की, आनंद की बात बोलते हैं।

हमने कश्मीर में जो धारा 370 को हटाया है, उससे वहाँ की माताओं, बहनों को एम्पावर किया है। उनको जो अधिकार नहीं दिए गए थे, वे अधिकार हमने दिलवाए हैं और उन अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत में बढ़ोतरी हुई है। आज शादी की उम्र के भी मानक तय किए गए हैं। क्या कारण है

कि आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए? क्या जरूरत है? यदि बेटा-बेटी एक समान हैं, तो यह हर जगह पर होना चाहिए, इसलिए बेटा-बेटी की शादी की उम्र एक समान हो, हम उस दिशा में आगे बढ़ें हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में यह सदन उस विषय में भी सही निर्णय लेकर हमारी माताओं, बहनों के कल्याण के लिए काम करेगा। आदरणीय सभापति जी, यह वर्ष गोवा के 60 वर्ष के एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज ज़रा उस चित्र के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र जहाँ भी होंगे, जरूर सुनते होंगे। आज गोवा के लोग मेरी बात को जरूर सुनते होंगे। जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, initiative लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती, तो गोवा को हिन्दुस्तान के आजाद होने के 15 साल बाद तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ। उस समय के, 60 साल पहले के अखबार, उस ज़माने की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब के प्रधान मंत्री, पंडित नेहरू की अंतरराष्ट्रीय छवि का क्या होगा, यह उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी, तो! इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक global leader की, शांतिप्रिय नेता की छवि है, वह चकनाचूर हो जाएगी। गोवा का जो होता है, होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े, झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान न हो। इसलिए जब वहाँ सत्याग्रहियों पर गोलियाँ चल रही थीं, विदेशी सल्तनत गोलियाँ चला रही थी, हिन्दुस्तान का हिस्सा, हिन्दुस्तान के ही मेरे भाई-बहन, उन पर गोलियाँ चल रही थीं, तब हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूँगा, मैं सेना नहीं भेजूँगा। सत्याग्रहियों की मदद करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह गोवा के साथ कांग्रेस का किया हुआ जुल्म है। और इससे गोवा को 15 साल ज्यादा गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया और गोवा के अनेक वीर पुत्रों को बलिदान देना पड़ा, लाठी-गोलियों के बीच जिंदगी बसर करनी पड़ी। ये हाल पैदा किए थे! पंडित नेहरू ने 15 अगस्त, 1955 को लाल किले से जो कहा था, मैं ज़रा quote करना चाहता हूँ। अच्छा होता, कांग्रेस के मित्र यहाँ होते, तो नेहरू जी का नाम सुन कर कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं आजकल बार-बार नेहरू जी को भी याद करता हूँ। नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको quote करता हूँ। "कोई धोखे में न रहे" -- भाषा देखिए -- "कोई धोखे में न रहे कि हम वहाँ फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आस-पास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचा कर ऐसे हालात पैदा करें कि हम मजबूर हो जाएँ फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज। हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को"। यह हुंकार, 15 अगस्त को गोवावासियों के aspirations के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान हैं। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था कि "जो लोग वहाँ जा रहे हैं"। लोहिया जी समेत सब लोग वहाँ सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश के सत्याग्रही जा रहे थे। हमारे कर्णाटक केसरी, जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था।

पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, 'जो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो...', देखिए, मज़ाक देखिए। अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा प्रयुक्त हुई है! उसमें कितना अहंकार है! वे कहते हैं, '...जो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन यह भी याद रखें कि अगर अपने को सत्याग्रही कहते हैं, तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह के पीछे फौजें नहीं चलतीं और न ही फौजों की पुकार होती है।' असहाय छोड़ दिया गया मेरे ही देश के नागरिकों को, यह गोवा के साथ किया गया। गोवा की जनता कांग्रेस के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकती है।

आदरणीय सभापति जी, हमें यहां freedom of expression पर भी बड़े भाषण दिए गए और आए दिन हमें freedom of expression के बारे में समझाया जाता है। मैं आज एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं और यह घटना भी गोवा के ही एक सपूत की है, गोवा की सम्माननीय धरती के एक बेटे की है। अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में क्या होता था, कैसे होता था, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की बातें करने वाले लोगों का आज मैं इतिहास खोल रहा हूं कि उन्होंने क्या किया। लता मंगेशकर जी के निधन से आज पूरा देश दुखी है, देश को बहुत बड़ी चोट लगी है। लता मंगेशकर जी का परिवार गोवा का है, लेकिन उनके परिवार के साथ कैसा सलूक किया, यह भी देश को जानना चाहिए। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी गोवा की गौरवपूर्ण संतान हैं, गोवा की धरती के बेटे हैं। वे All Indian Radio में काम करते थे, लेकिन उन्हें All India Radio से निकाल दिया गया। उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था कि उन्होंने वीर सावरकर की देशभक्ति से भरी एक कविता की All India Radio पर प्रस्तुति दी थी।...(व्यवधान)... आप देखिए! हृदयनाथ जी ने अपने एक interview में बताया, उनका वह interview available है, जिसमें उन्होंने कहा, जब वे सावरकर जी से मिले कि मैं आपका गीत गाना चाहता हूं, तो सावरकर जी ने उनसे कहा, "क्या तुम मेरी कविता गा कर जेल जाना चाहते हो?" हृदयनाथ जी ने देशभक्ति से भरी उनकी कविता को संगीतबद्ध किया, उसके बाद आठ दिन के अंदर उनको All India Radio से निकाल दिया गया।...(व्यवधान)... यह आपका freedom of expression है! ये स्वतंत्रता की आपकी झूठी बातें देश के सामने आपने रखी हैं! कांग्रेस की सरकारों के दौरान किस प्रकार के जुल्म हुए, ऐसा सिर्फ गोवा के बेटे, हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ ही नहीं हुआ, इसकी सूची काफी लम्बी है। मजरूह सुल्तानपुरी जी को पंडित नेहरू की आलोचना करने के लिए एक साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया।...(व्यवधान)... नेहरू जी के रवैये की आलोचना करने के लिए प्रोफेसर धर्मपाल जी को जेल में डाल दिया गया था।...(व्यवधान)... प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार जी को emergency में इन्दिरा जी के सामने न झुकने के कारण और emergency के पक्ष में न बोलने के कारण आपातकाल में निकाल दिया गया था।...(व्यवधान)... हम सभी जानते हैं कि एक विशेष परिवार के खिलाफ अगर कोई थोड़ी सी भी आवाज़ उठाता है या ज़रा भी आंख ऊँची करता है, तो क्या होता है। सीताराम केसरी जी के बारे में हम सभी भली-भांति जानते हैं, उनके साथ क्या हुआ, यह हमें पता है।

आदरणीय सभापति जी, मेरी इस सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि भारत के उज्ज्वल भविष्य पर भरोसा करें, 130 करोड़ देशवासियों की सामर्थ्य पर हम भरोसा करें। बड़े लक्ष्य लेकर इसी सामर्थ्य के आधार पर देश को नई ऊँचाई पर ले जाने के लिए हम कृतसंकल्पी बनें।

आदरणीय सभापति जी, हमें मेरे-तेरे, अपने-पराये इस परम्परा को खत्म करना होगा और एक मत से, एक भाव से, एक लक्ष्य से, एक साथ चलना, यही देश के लिए समय की मांग है। एक स्वर्णिम काल है, पूरा विश्व भारत की तरफ बड़ी आशा और बड़े गर्व से देख रहा है। ऐसे समय में हम मौका गंवा न दें- देशवासियों के कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई अवसर आने वाला नहीं है- यह मौका हम पकड़ लें, 25 साल की यात्रा हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है, हमारे देश के लिए, हमारी परम्पराओं के लिए हम गौरव करें। हम बड़े विश्वास के साथ एक साथ मिलकर चलेंगे। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है -

"सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।"

यानी हम साथ चलें, साथ चर्चा करें, मिलकर हर कार्य करें, इसी आह्वान के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अनुमोदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और सभी आदरणीय सदस्यों ने जो सहभाग किया, अपने विचार रखे, उनका भी धन्यवाद करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendments (Nos. 1 to 6) and Amendments (Nos. 21 to 24) by Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya; are you withdrawing the amendments or shall I put them to vote?

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): Sir, I am pressing the Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 1 to 6 and 21 to 24) by Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya to vote.

The Amendments (Nos. 1 to 6 and 21 to 24) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 7 to 14) are by Shri Shaktisinh Gohil; not present. I shall now put the Amendments (Nos. 7 to 14) to vote.

The Amendments (Nos. 7 to 14) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 15 to 20) by Shrimati Jharna Das Baidya; are you pressing the Amendments?

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 15 to 20) by Shrimati Jharna Das Baidya to vote.

The Amendments (Nos. 15 to 20) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 34 to 41) by Shri Elamaram Kareem; are you withdrawing the Amendments or pressing them?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I am pressing them.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 34 to 41) by Shri Elamaram Kareem to vote.

The Amendments (Nos. 34 to 41) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 42 to 51) by Shri M. Shanmugam; are you pressing the Amendments?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 42 to 51) by Shri M. Shanmugam to vote.

The Amendments (Nos. 42 to 51) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 52 to 59) by Shri K. Somaprasad; are you pressing the Amendments?

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 52 to 59) by Shri K. Somaprasad to vote.

The Amendments (Nos. 52 to 59) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 70 to 73) by Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा ...(व्यवधान)... उन्होंने दुनिया भर की बात की ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Are you pressing or withdrawing the Amendments? ...(Interruptions).. If you are withdrawing them, I would not put them to vote. ...(Interruptions).. Mr. Bikash Bhattacharya, I will have to name you. This is not the way. I have been noticing that continuously, since morning, you have been suffering with this problem and making us suffer too. If you don't like it, then walk out. ...(Interruptions).. I can't do anything else. I can't do anything because it is for the House. If you don't like a particular speech, don't like it. I am not forcing you.

1.00 P. M.

Shri Digvijaya Singh, are you withdrawing the Amendments?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: No, Sir. I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 70 to 73) by Shri Digvijaya Singh to vote.

The Amendments (Nos. 70 to 73) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 74 to 81) have been moved by Shrimati Priyanka Chaturvedi. Are you pressing?

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Yes, Sir. I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 74 to 81) by Shrimati Priyanka Chaturvedi to vote.

The Amendments (Nos. 74 to 81) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 82 to 89) have been moved by Shri Tiruchi Siva. Are you withdrawing the Amendments or pressing them?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): I am pressing my Amendments.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 82 to 89) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The Amendments (Nos. 82 to 89) were negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 90 to 99) have been moved by Shri K.C. Venugopal. He is not there.

The Amendments (Nos. 90 to 99) were negatived.

MR. CHAIRMAN: As all the Amendments are negatived, I shall now put the Motion to vote. The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

"That the Members of the Rajya Sabha presented in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on January 31, 2022."

The motion was adopted.
